खाड़ी को पुनः आकार देना

लेखक - सुजन आर चिनॉय (पूर्व राजदूत, वर्तमान में रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के महानिदेशक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

14 जनवरी, 2020

"भारत अमेरिका-ईरान तनाव में किसी का पक्ष नहीं ले सकता। लेकिन नई दिल्ली को अपनी क्षेत्रीय कूटनीति को सक्रिय करना होगा।"

इराक में 3 जनवरी को हुए ड्रोन हमले में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के कुद्स बल के प्रमुख जनरल कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था, लेकिन इराक में अल असद और इरबिल में दो अमेरिकी ठिकानों पर 8 जनवरी की सुबह जवाबी कार्रवाई में कई मिसाइल हमलों के बाद युद्ध के बादल अब छंटते दिख रहे हैं। अमेरिका के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले ने कहा कि मिसाइलों का उद्देश्य संरचनात्मक क्षति, वाहनों तथा विमानों को नष्ट करना और कर्मियों को मारना था। हालाँकि, अमेरिका ने किसी भी हताहत से इंकार किया है, लेकिन ईरान ने दावा किया है कि इस हमले में कम से कम 80 लोग मारे गए हैं।

ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने ट्वीट कर के बताया कि ईरान ने 'आत्मरक्षा में आनुपातिक उपाय किया और उसको अच्छे से अंजाम तक पहुँचाया।' उन्होंने आगे कहा कि 'हम इस तनाव में वृद्धि या युद्ध नहीं चाहते हैं।' राष्ट्रपति ट्रम्प ने इसके बाद एक बहुप्रतीक्षित बयान दिया कि इस हमले में कोई भी अमेरिकी 'हताहत नहीं हुआ है' और उसके सैन्य ठिकाने को 'मामूली क्षति' हुई है, साथ ही इन्होंने कहा कि "ईरान पीछे हटता दिख रहा है जो संबंधित सभी पक्षों और दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है।"

अगर हम दोनों देशों के बयानों पर ध्यान दे तो पाएंगे कि दोनों देश युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। अपनी ओर से ईरान के एक राष्ट्रीय नायक की हत्या का बदला लेने के दावे का उद्देश्य जनता की गहरी भावना का निर्माण करना था।

रिपोर्ट्स का सुझाव है कि सुलेमानी ईरान और सऊदी अरब के बीच सामंजस्यपूर्ण वार्ता के लिए एक मिशन पर था। उनकी हत्या सोची समझी चाल है, क्योंकि सुलेमानी इस क्षेत्र में अमेरिका के लिए एक कांटा था। अमेरिका ने ईरान में शासन के खिलाफ हाल के महीनों में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद बढ़ते घरेलू असंतोष और प्रदर्शनों को भुनाने की उम्मीद की थी, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि सुलेमानी की मृत्यु और अमेरिका के साथ तनाव ने शासन के पीछे ईरानी लोगों को एकजुट कर दिया था। लेकिन ईरान में शासन-विरोधी प्रदर्शनों का ताजा प्रकोप इस बात को दर्शाता है कि ईरान द्वारा 8 जनवरी को एक यूक्रेनी एयरलाइनर को 'अनजाने में' मार गिराना, इसके आंतरिक स्थिति के विद्रोहक होने की पुष्टि करता है।

इसके निपटान में ईरान के पास कई विकल्प थे, लेकिन इराक में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले ने सब बंद कर दिए। लेबनान, सीरिया और यमन में क्षेत्रीय निकटता का उपयोग जोखिम भरा रहेगा और यह संघर्ष को बढ़ा सकता है, जो ईरान के लिए पूरी तरह अप्रत्याशित परिणाम सामने लाएगा।

देखा जाये तो, यदि ईरान के प्रतिशोध के कारण अमेरिका हताहत होता तो अमेरिका चुनिंदा सैन्य और अन्य ठिकानों पर और हमले कर सकता था। ट्रम्प ने पहले ईरान को चेतावनी दी थी कि अमेरिका ईरान में 52 साइटों को लक्षित करेगा। यह संख्या 1979 में तेहरान में अमेरिकी दूतावास की घेराबंदी के दौरान ईरान द्वारा उठाए गए 52 अमेरिकी बंधकों का एक प्रतीकात्मक अनुस्मारक थी।

ट्रम्प ईरान के परमाणु हथियार क्षमता के अधिग्रहण को पूरा नहीं होने देने के पक्ष में दिख रहे हैं। व्हाइट हाउस में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जो पहले शब्द बोले, वह यह था कि 'जब तक मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ, तब

तक ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी।'

विशेष रूप से, यहाँ तक कि जब ईरान ने सार्वजनिक रूप से सुलेमानी की हत्या के बाद संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) से दूर जाने का इरादा जताया था, तो इस बात को लेकर काफी सावधान था कि वह एनपीटी और आईएईए निरीक्षणों के लिए अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आश्वस्त करे।

यदि ईरान के पास क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, तो अमेरिका का भी इस क्षेत्र में अपने कई ठिकानों और वाहक बलों के अलावा इजरायल का एक मजबूत सहयोग प्राप्त है। इजराइल के प्रति ईरान की अडिग दुश्मनी को देखते हुए, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सुलेमानी की हत्या के बाद ट्रम्प की कार्रवाई की स्पष्ट प्रशंसा की थी। ईरान के प्रतिशोध के बाद, उन्होंने कहा था कि अगर हमला हुआ तो इजरायल के पास ईरान को 'कुचलने' की पूरी क्षमता है। ईरान और अमेरिका के बीच कोई भी सशस्त्र टकराव इराक में नाजुकता को बिगाड़ते हुए केवल शिया, सुन्नियों और कुर्दों के बीच दोषपूर्णता को गहरा करेगा।

इराकी धरती पर सभी विदेशी सैनिकों की उपस्थिति को समाप्त करने के लिए इराकी संसद के गैर-बाध्यकारी संकल्प से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि कोई भी इससे अनुमान लगा सकता है कि यह न केवल अमेरिका और उसके सहयोगियों के पर, बल्कि ईरान पर भी लक्षित है।

केयर (CARE) रेटिंग्स के अनुसार, छंटते युद्ध के बादल अव्यवस्थित ऊर्जा बाजार को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता, जहाँ एक डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से भारत के आयात बिल में लगभग 1.6 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है।

अपने संसद भाषण में, इराकी पीएम आदिल अब्दुल-महदी ने कहा था कि सुलेमानी ईरान और सऊदी अरब के बीच सुलह पर चर्चा करने के लिए उनसे मिलने के लिए बगदाद में थे। हालाँकि यह थोड़ा अजीब लग सकता है कि क्योंकि इस्लामी दुनिया में नेतृत्व के लिए दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता चल रही है।

इसी समय, वास्तविकता यह है कि सऊदी अरब यमन में एक सैन्य जीत की मृगतृष्णा का पीछा कर रहा है। सितंबर में अबकाक और खुरासियों में दो अरामको तेल सुविधाओं पर ड्रोन हमलों और 'सुलेमानी की अप्रत्याशित हत्या' जैसे घटनाओं के बाद, सऊदी अरब ईरान के साथ एक सौदे पर सहमत हो सकता है जो यमन में नाजुक हालात से गौरव के साथ वापस होने का मौका देता है।

रूस सीरिया में ईरान की नीतियों का समर्थन करता है। इसने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन के रूप में सुलेमानी पर अमेरिकी हमले की निंदा की, हालाँकि चीन ने अब तक इससे दूरी बना रखी है। चीन, ईरान का सबसे बड़ा तेल बाजार, एक हथियार आपूर्तिकर्ता और एक शीर्ष व्यापार भागीदार बना हुआ है। जेसीपीओए की सुरक्षा के लिए चीन के समर्थन से ईरान आश्वस्त था। हालाँकि, 27 दिसंबर को बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के बीच, रूस, चीन और ईरान पहले चार दिन की त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास के लिए एक साथ ओमान की खाड़ी में आए। इसका उद्देश्य अमेरिका को एक मजबूत संदेश देना था कि ईरान अलग-थलग नहीं है।

हर बार एक क्षेत्रीय संकट रहा है, चाहे वह 1950 के दशक में साम्यवाद की लहर हो, 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण हो या हाल ही में 9/11 के बाद आतंक पर वैश्विक युद्ध हो, लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान नए हथकंडे के साथ लौट आया है। हालांकि, अमेरिका पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अपनी ही मजबूरियों से ग्रसित है और यह अपने दोहरे रवैये से भरे इतिहास के लिए भी बदनाम है।

यह संदेहजनक है कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ पाकिस्तान के समर्थन को अपनाएगा। इसलिए इसकी संभावना अधिक है कि पाकिस्तान रूस, चीन और ईरान के बीच किसी भी उभरती हुई शक्ति की ओर होगा।

भारत इसका पक्ष नहीं ले सकता। भारत के लिए ऊर्जा की आपूर्ति और खाड़ी में इसके विशाल प्रवासी लोगों की सुरक्षा और बचाव का अत्यधिक महत्व है। ईरान के प्रति सहानुभूति के साथ भारत के पास शिया आबादी भी काफी है।

क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए प्रस्ताव ईरान के होर्मुज पीस एंडेवर (HOPE) से लेकर अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा संरक्षण (IMSC) तक संबंधित है। रूस के पास फारस की खाड़ी में सामूहिक सुरक्षा का भी प्रस्ताव है। एक बड़े और प्रभावशाली देश के रूप में विस्तारित पड़ोस नीति के साथ, परिणामों को आकार देने के लिए अपनी क्षेत्रीय कूटनीति को सक्रिय करना भारत के हित में होगा।

अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ता विवाद

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के शीर्ष सुरक्षा और खुफिया कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया गया।
- जनरल सुलेमानी हवाई हमले में मारे गए हैं, जिसकी जिम्मेदारी अमेरिका ने ली है। बगदाद के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास सड़क पर ड्रोन द्वारा हमला की गई थी। इस विस्फोट में इराक में ईरानी समर्थित मिलिशिया के डिप्टी कमांडर अबू महदी अल-मुहांडिस सहित अन्य लोग भी मारे गए, जिन्हें पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के नाम से जाना जाता है।
- 62 साल के सुलेमानी, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के कुद्स बल के प्रभारी थे, जिसे यूएस ने पिछले साल अप्रैल में एक विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया था। कुद्स बल अन्य देशों में ईरानी मिशनों को अंजाम देता है, जिनमें गुप्तचर भी शामिल होते हैं।
- इससे पहले ईरान ने 2015 के परमाणु समझौते में संवर्धित यूरेनियम के उत्पादन को लेकर तय की गई सीमा का उल्लंघन किया था और यूरोप को जवाबी कार्रवाई करने के खिलाफ आगाह किया था।
- इसके साथ ही माना जा रहा है कि ईरान P5+1 और यूरोपीय संघ के साथ 2015 में हुए ऐतिहासिक समझौते को तोड़ने की दिशा में आगे बढ़ गया है, जिस दौरान यूरेनियम भंडारण की सीमा तय की गई थी।
- गौरतलब हो कि ईरान ने मई में घोषित अपनी योजना के आधार पर 300 किलोग्राम की सीमा पार कर ली है।
- ईरान द्वारा निर्धारित सीमा (3.7%) को पार किए जाने और 4.5 प्रतिशत संवर्धन करने की घोषणा देश के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रवक्ता बेहरूज कमालवंदी ने की।
- कमालवंदी ने संकेत दिया है कि इस्लामी गणराज्य कुछ समय तक संवर्धन के इस स्तर को बरकरार रख सकता है, जो एक परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90 प्रतिशत के स्तर से काफी नीचे है।

पृष्ठभूमि

- अमेरिका ने पिछले साल परमाणु सौदे से खुद को अलग कर लिया था और ईरान के महत्त्वपूर्ण तेल निर्यात और वित्तीय लेन-देन तथा अन्य क्षेत्रों पर सख्त प्रतिबंध फिर से लगा दिए थे।
- ईरान, जिसने समझौते को बचाने के लिए इसके अन्य साझेदारों पर दवाब बढ़ाने की कोशिश के तहत घोषणा की थी कि वह संवर्धित यूरेनियम एवं हैवी वाटर भंडार पर लगाई गई सीमा को अब नहीं मानेगा।
- साथ ही धमकी दी थी कि वह और परमाणु प्रतिबद्धताओं को भी नहीं मानेगा जब तक कि समझौते के शेष साझेदार- ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी और रूस इन प्रतिबंधों से उसे छुटकारा नहीं दिलाते, खासकर तेल की बिक्री पर लगे प्रतिबंध से।
- वर्ष 2015 में हुए इस सौदे के तहत् ईरान ने कभी भी परमाणु बम नहीं रखने, उसके परमाणु कार्यक्रम पर लगाई गई कठोर सीमाओं को मानने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटाए जाने के बदले में आईएईए को निरीक्षण करने देने की प्रतिबद्धता जताई थी।

होर्मुज जलडमरूमध्य

- इसे ओरमुज जलडमरूमध्य के नाम से भी जाना जाता है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- यह ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है और यह 55 से 95 किमी. तक चौड़ा है।
- इसमें प्रमुख रूप से कीश्म, होर्मुज और हेंजम (हेंग्म) द्वीप स्थित हैं।
- सऊदी अरब, ईरान, यू.ए.ई., कुवैत और इराक से निर्यात किये जाने वाले अधिकांश कच्चे तेल को इसी जलमार्ग के माध्यम से भेजा जाता है।

संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA)

- ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिये वर्ष 2015 में ईरान तथा P5+1 देशों (अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्राँस, रूस और जर्मनी) के मध्य एक समझौता किया गया। इसे वियना समझौता के नाम से जाना जाता है।
- इसके अनुसार ईरान अपने परमाणु संयंत्रों की नियमित जाँच के लिये राजी हुआ, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वहाँ परमाणु हथियार बनाने पर काम नहीं चल रहा है।
- इस समझौते में ईरान द्वारा परिष्कृत यूरेनियम भंडार को 96 प्रतिशत तक घटाना और अपने सभी संयंत्रों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के लिये खोलना शामिल है।
- इस समझौते के तहत ईरान ने अपने करीब नौ टन अल्प संवर्द्धित यूरेनियम भंडार को कम करके 300 किलोग्राम तक करने की शर्त स्वीकार की थी।
- इस समझौते का मकसद परमाणु कार्यक्रमों को रोकना था। इन शर्तों के बदले में पश्चिमी देश ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटाने पर सहमत हुए थे।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. होर्मुज जलडमरूमध्य के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
2. यह इराक को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है।
3. अरब देशों के अधिकांश कच्चे तेल का व्यापार इस जलमार्ग के माध्यम से होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 1 और 3

(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements in the context of the Strait of Hormuz.

1. It connects the Persian Gulf to the Gulf of Oman and the Arabian Sea.
2. It separates Iraq from the Arabian Peninsula.
3. Most of the crude oil trade in Arab countries is done through this searoute.

Which of the above statements is/are correct?

(a) 1 and 2 (b) 1 and 3

(c) Only 3 (d) 1, 2 and 3

नोट : 13 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'अमेरिका-ईरान विवाद खाड़ी क्षेत्र में वर्तमान संकट का एक बड़ा कारण तो है, किन्तु इस क्षेत्र में मौजूद गुटों के कारण खाड़ी संकट कई वर्षों से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में बना हुआ है।' क्या ऐसे में इस संकट का स्थायी समाधान खाड़ी में मौजूद सम्बन्धों को पुनर्निर्धारित करना हो सकता है? टिप्पणी कीजिए।

(250 शब्द)

'The US-Iran dispute is one of the major reasons for the current crisis in the gulf region, but due to the factions present in this region, the gulf crisis has been prevalent in direct and indirect form for many years.' Can reassessement of the existing relationships be the permanent sollution of this crisis in the gulf? Comment (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।